व्यापार सुधार जरूरी

बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था वैश्वीकरण का आधार है. लेकिन आज यह व्यवस्था संकटग्रस्त है. ऐसे में इसकी नियामक संस्था विश्व व्यापार संगठन में ठोस सुधारों की जरूरत है. संरक्षणवादी नीतियों के तहत एकतरफा शुल्कों की घोषणा और उनकी प्रतिक्रिया के कारण व्यापार युद्ध की स्थिति बनी हुई है. अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगठन में कोई सहमति नहीं बन पा रही है तथा कई विवाद लंबित हैं. भारत ने इन समस्याओं को रेखांकित करते हुए इन्हें अस्तित्व के लिए चुनौती कहा है. इस संगठन में सुधार के प्रयास भी असंतुलित हैं तथा इनसे विकासशील और अविकसित देशों को ही नुकसान होने की आशंका है. संरक्षणवादी नीतियों का सर्वाधिक नकारात्मक असर गरीब देशों को ही भुगतना पड़ रहा है. दिल्ली में 22 सदस्य देशों की बैठक में भारत ने एकजुटता का आह्वान किया है. किसी सदस्य देश द्वारा मनमाने ढंग से एकतरफा फैसला लेने से संबंधित नियमों में बदलाव करने का एक प्रस्ताव भी भारत ने इस बैठक से पहले दिया है. इस पहल को अनेक देशों समेत चीन और दक्षिण अफ्रीका का भी समर्थन है. अमेरिका इसका विरोध कर रहा है. राष्ट्रपति समेत ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्य भारतीय शुल्कों पर आपत्ति करते रहे हैं. इसके अलावा विकसित देशों ने अक्सर भारत और अन्य कुछ देशों के कृषि उत्पादों को लेकर भी सवाल उठाया है. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सभी पक्षों के लिए लाभदायक बनाने की बहस में यह बात याद रखी जानी चाहिए कि 2001 में दोहा बैठक में कृषि अनुदान, बाजार में पहुंच और सेवाओं को लेकर एजेंडा तय हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य विकास था. लेकिन, ऐसा लगता है कि समय बीतने के साथ इन मुद्दों पर विकसित देशों की रुचि कमतर होती गयी है. अब उनका अधिक ध्यान अपने देशों के कॉरपोरेट हितों को साधने पर है, न कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर. आम तौर पर संगठन में किसी एजेंडे या नियमन को व्यापक सहमति से ही लाने की परिपाटी रही है. विकसित देश अल्पविकसित देशों को अपने पाले में लाने में सफल रहते हैं, जैसा कि दिसंबर, 2017 की बैठक में हुआ था. ये देश आर्थिक और वित्तीय रूप से विकसित देशों पर निर्भर हैं, सो उनके लिए विरोध करना बेहद मुश्किल होता है. इ-कॉमर्स, मछली पालन अनुदान, विशेष दर्जा, विवाद निपटारे की व्यवस्था आदि मुद्दों पर बैठकें होनी हैं. इनमें विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच तनातनी के पूरे आसार हैं. पहले की बैठकों में विकासशील देश एकजुटता के कारण ही अपने पक्ष में निर्णय कराने में सफल रहे हैं. भारत लगातार एकता बनाने की कोशिश में है. अब देखना यह है कि क्या ऐसा हो पायेगा, क्योंकि अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों की तरह विश्व व्यापार संगठन भी ताकतवर देशों के लिए स्वार्थ पूरा करने की जगह बन चुका है. अगर सकारात्मक सुधारों के लिए भारत के आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वैश्विक वाणिज्य एवं व्यापार की वर्तमान अस्थिरता गंभीर होती जायेगी.

अगर सकारात्मक सुधारों के लिए भारत के आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वैश्विक वाणिज्य एवं व्यापार की वर्तमान अस्थिरता गंभीर होती जायेगी .

नयी सरकार की आर्थिक चुनौतियां

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग द्वारा जारी नवीनतम मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियां नजर आती हैं. पिछले पांच वर्षों के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 7.2 एवं 7.0 प्रतिशत तक आ चुकी है. नवीनतम त्रैमासिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत है. इस तरह, यह घटती वृद्धि दर लगातार चौथे वर्ष भी जारी है. अब हम सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब भी बरकरार नहीं रख सकेंगे, क्योंकि चीन की आर्थिक वृद्धि दर हमसे थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

इन्हीं तीन वर्षों के दौरान कृषि में सकल मूल्य वर्धित (ग्रॉस वैल्यू ऐडेड-जीवीए) भी 6.3 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 5.0 प्रतिशत से होते हुए 2.7 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और यह चिंता की दूसरी वजह है. क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 के दौरान खाद्य मूल्यस्फीति वर्ष 1991 के पश्चात निम्नतम स्तर पर थी. पिछले वर्ष के एक बड़े हिस्से में फल, सब्जियों, दालों तथा चीनी में नकारात्मक मूल्यस्फीति यानी मूल्य अपस्फीति की स्थिति रही. पिछले कई वर्षों से ग्रामीण मजदूरी वृद्धि पांच प्रतिशत से कम रही है. इसने ग्रामीण मांग पर असर डालते हुए उन व्यवसायों का प्रदर्शन भी धीमा कर दिया है, जो स्वस्थ ग्रामीण मांग पर निर्भर होते हैं. इनमें तेजी से बिकनेवाली उपभोक्ता वस्तुएं (एफएमसीजी) जैसे, साबुन, टूथपेस्ट, बालों का तेल, बिस्कुट इत्यादि के अलावा दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. नतीजतन, इन्हें बनानेवाली कंपनियों की आय वृद्धि दर पिछले दो वर्षों में सबसे नीचे आ चुकी है और दोपहिया वाहनों की बिक्री की मासिक वृद्धि में पिछले एक वर्ष से भी अधिक अवधि से गिरावट का रुख जारी है, जो नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है.

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, चिंता की तीसरी वजह पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू खाते के घाटे में जारी लगातार वृद्धि है, जो 0.6 से क्रमशः 1.9 होते हुए जीडीपी के 2.6 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है. इस स्थिति का अर्थ यह है कि निर्यातों से हमारी आय हमारे बढ़ते आयातों के खर्चे पूरे करने में असमर्थ है. वर्ष 2014 से लेकर मार्च 2019 तक के पांच वर्षों के दौरान निर्यातों में शुद्ध वृद्धि शून्य रही है. निर्यात सीधी तरह घरेलू विनिर्माण संबंधी गतिविधियों से संबद्ध होते हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार महीनों से लगातार गिरता औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इस मार्च में नकारात्मक हो चुका है. पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) के उत्पादन में तीव्र नकारात्मक वृद्धि तो खास चिंता की वजह बन चुकी है, क्योंकि मार्च महीने का सूचकांक नकारात्मक 8.7 के स्तर पर आ चुका है. सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार, यह तथ्य कि पिछले तीन महीनों में भारतीय मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के अर्थ में ज्यादा मजबूत हुई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू खाते के बढ़ते रुझान की चुनौतियों को और विषम कर रहा है. यहां यह याद रखना भी प्रासंगिक होगा कि कच्चे तेल के बाद आयातों की अगली सबसे बड़ी वस्तु मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स माल हैं.

चिंता का चौथा सबसे बड़ा कारण जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत निवेश में आयी जड़ता है. अतीत में यह अनुपात 35 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, मगर वर्तमान में 28 प्रतिशत पर ठहरा है. निजी निवेश व्ययों में वृद्धि भी लगभग शून्य हो चुकी है. इसका अर्थ यह है कि नयी क्षमताओं का सृजन नहीं हो रहा है और न ही नये व्यावसायिक उपक्रम आरंभ किये जा रहे हैं. गिरते निवेश अनुपात के परिणामस्वरूप भारत का संभाव्य (पोटेंशियल) जीडीपी संभवतः 8 प्रतिशत से गिरकर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर उतर आया है, जिसका मतलब यह है कि इसके बाद अब कोई भी आघात अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा. इसका एक यह लक्षण सामने है कि उपभोक्ता मूल्य आधारित एवं थोक मूल्य आधारित दोनों किस्म की मुद्रास्फीतियां वृद्धि के रुझान पर हैं. मंत्रालय की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जीडीपी डिफ्लेटर (वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर का एक पैमाना) भी ऊपर चढ़ता जा रहा है.

साफ है कि अगली केंद्रीय सरकार के लिए अर्थव्यवस्था उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य रथिन रॉय ने चेताया भी है कि भारत मध्य-आय फंदे में पड़ने का जोखिम झेल रहा है. उनके अनुसार, पिछले दो दशकों के दीर्घावधि रुझान बताते हैं कि दक्षिण कोरिया एवं जापान के विपरीत भारत एक निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था नहीं बन सका है. यह घरेलू उपभोग वृद्धि पर निर्भर रहा है, मगर यह वृद्धि मुख्यतः सर्वोच्च 10 करोड़ उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की ही पूर्ति करती रही है. इनमें कारें, दोपहिया वाहन, हवाई यात्राएं जैसी चीजें शामिल हैं. पर अब वह मांग भी घट रही है. ऑटो क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने में अपनी मांग में 17 प्रतिशत की गिरावट देखी, जो सात वर्षों में सर्वाधिक है. यहां तक कि मार्च माह में घरेलू हवाई यात्राओं में भी वृद्धि दर शून्य रही, जिसकी एक वजह तो जेट एयरवेज की बंदी भी थी. पर यह स्थिति पिछले चार वर्षों में दहाई अंकों की वृद्धि (विश्व में सर्वाधिक) के बाद उत्पन्न हुई है. डॉ रॉय कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को तीव्र करने का भार या तो उपभोग वृद्धि का फलक विस्तृत कर अथवा निर्यातों को बढ़ा कर वहन करना होगा.

वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था को चार कारक चाहिए- उपभोग, निर्यात, निवेश तथा इसे चालू रखने हेतु सरकार. सरकार का योगदान राजकोषीय सीमाओं में आबद्ध होता है. भारत की राजकोषीय स्थिति पांच वर्ष पूर्व से बेहतर है, पर यह संतोष की वजह नहीं है. सार्वभौमिक आय, स्वास्थ्य बीमा, ऋण माफी के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनर्पूंजीकरण जैसी जिम्मेदारियों के रहते सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अनिश्चित काल तक निवेश द्वारा आर्थिक गतिविधियों में जान फूंकती रहेगी. इसमें शक नहीं कि सड़कों, रेलों तथा जलमार्गों पर बड़े व्यय से दीर्घावधि में और भी कई फायदे होते हैं, पर यदि हम 8-जोड़ प्रतिशत की समावेशी वृद्धि पर केंद्रित हैं, तो ऐसे निवेश की एक सीमा है. नयी सरकार द्वारा सबसे पहले भारी सरकारी रिक्तियों के विरुद्ध बड़े पैमाने की नियुक्तियां एवं ग्रामीण संकट को संबोधित करने जैसे काम होने चाहिए. इन अल्पावधि प्राथमिकताओं के साथ ही हमें अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त चार नहीं, तो कम से कम उपभोग एवं निवेश के दो कारकों में जान डालने की जरूरत है.

(अनुवाद: विजय नंदन)

अजीत रानाडे
सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन
editor@thebillionpress.org

अगली केंद्रीय सरकार के लिए अर्थव्यवस्था उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य रथिन रॉय ने चेताया भी है कि भारत मध्य-आय फंदे में पड़ने की जोखिम झेल रहा है .

भारत-फ्रांस सैन्याभ्यास और चीन

आम चुनाव की सरगर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर है. इस चुनाव के परिणाम के बाद नयी सरकार का गठन होगा. अगर पिछले दो महीने का जायजा लिया जाये, तो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द इस लोकसभा चुनाव में फ्रांस का राफेल युद्धपोत, चीन और पाकिस्तान रहे हैं. तीनों का संबंध भारत की सुरक्षा व्यवस्था से है. इन तमाम विवादों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अरब सागर पर अभी तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास किया है. अभ्यास के दौरान चीन का बिना नाम लिये एक सशक्त मैसेज भी दिया गया है. यह समझना जरूरी है कि सामरिक नजरिये से भारत-फ्रांस सयुक्त अभ्यास का मतलब क्या है?

भारत और फ्रांस की नौसेना ने विमानवाहक पोत 'चार्ल्स डे गॉले' के साथ हिंद महासागर में बीते शुक्रवार सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया. रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं. चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में दबदबे से भारत और फ्रांस चिंतित हैं. ऐसे में इतने व्यापक युद्धाभ्यास को चीन को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. फ्रांसीसी पोत की कमान संभाल रहे रियर एडमिरल ओलिवर लेबास ने कहा, 'यह युद्धाभ्यास 2001 में शुरू हुए अभियान का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है. हम इस क्षेत्र में स्थिरता ला सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी मायने रखता है. एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों के बीच ज्यादातर व्यापार समुद्र के जरिये ही होता है. हिंद महासागर में भारत का पारंपरिक दबदबा चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहा है. चीन ने समुद्री मार्गों के करीब युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती की है.

फ्रांसीसी नौसेना के हेड रियर एडमिरल दिदिर मालटरे ने कहा कि हिंद महासागर में चीन आक्रामक नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में स्थिति अलग है. दरअसल फ्रेंच अधिकारी का इशारा दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर पड़ोसी देशों के साथ उपजे विवाद पर था. चीन द्वारा नये सिल्क रोड व्यापार गलियारे का निर्माण, जिसमें हिंद महासागर भी शामिल है, एक रणनीति है जो मुख्य तौर पर आर्थिक से ज्यादा किसी और उद्देश्य को लेकर है. अगले 10 से 15 साल में ऐसे हालात बन सकते हैं, जिससे तनाव पैदा हो सकता है. पिछले महीने फ्रांस ने ताइवान जलडमरूमध्य में अपना एक युद्धपोत भेजकर चीन को नाराज कर दिया था. चीन की नेवी ने शिप को इंटरसेप्ट किया और पेइचिंग ने इस पर एक आधिकारिक विरोध भी जताया था, जबकि फ्रांस ने कहा कि वह अपने नौवहन की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा था और उसका हिंद महासागर में अभ्यास से कोई कनेक्शन नहीं है.

फ्रांस शीत युद्ध के बाद भारत का सबसे मुखर सैनिक सहयोगी देश रहा है. यहां तक कि 1980 के दशक में जब भारत का सैनिक व्यापार केवल रूस के साथ था, तब भी फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा देश था, जो भारत को सैनिक सहायता प्रदान करता था. भारत के आण्विक प्रयोग के बाद जब दुनिया कि नजरें भारत के विरुद्ध हो गयी थीं, तब फ्रांस ने ही मुख्य भूमिका निभायी और अमेरिका को मनाने में सफल हुआ कि भारत का शक्ति संवर्धन पश्चिमी दुनिया के लिए भी जरूरी है. उसके बाद भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बदल गयी. पुनः 2001 के बाद भारत ने दीर्घकालीन नौसैनिक सयुंक्त व्यवस्था शुरू की. यह नवीनतम अभ्यास उसी का हिस्सा है. चीन दुनिया के नौसैनिक नियमों को नहीं मानता. वहीं फ्रांस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों में से है. वर्षों तक वियतनाम और साउथ चीन सी में फ्रांस की हुकूमत चलती थी. शुरू से ही फ्रांस नौसैनिक मानकों पर कई देशों से आगे था.

भारत और फ्रांस के बीच बन रहे समीकरण का तत्कालीन कारण तो चीन है, लेकिन यह महज चीन तक सीमित नहीं है. नयी विश्व व्यवस्था में भारत और फ्रांस एक मिडिल किंगडम की भूमिका में हैं. फ्रांस यूरोप के लिए मिडिल पावर है, तो भारत एशिया के लिए. दोनों के आपसी मिलन से यह वैश्विक शक्ति के रूप में बदल जाता है.

चीन की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग नीति की सोच भारत विरोध पर टिकी हुई है. वर्तमान चीन के राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण योजना वन बेल्ट रोड ही है. सिल्क रूट को पुनः जीवित करने की योजना भी चीन की बेहद खतरनाक और भारत विरोधी है. चीन कहता है कि यह केवल दुनिया को आर्थिक रूप से जोड़ने की योजना है, लेकिन अगर पांच वर्षों के ड्रैगन की चाल को नापा जाये, तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं. भारत के इर्द-गिर्द चीन का जाल पूरी तरह से फैलता गया है.

डोकलाम विवाद के बाद चीन ने पाकिस्तान की भारत विरोधी ताकतों को मदद देने की गति को और तेज कर दी. लेकिन, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उससे चीन के दांत कुछ खट्टे जरूर हुए होंगे. आतंकवाद के मसले पर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल होना एक तरह से चीन की कूटनीतिक हार ही है. और ठीक उसके बाद ही फ्रांस के साथ भारत का यह नौसैनिक अभ्यास, जिसमें आण्विक पनडुब्बी की शक्ति का परीक्षण किया गया है, भारत की मजबूती दर्शाता है. यह सब कुछ भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह सब भारतीय प्रधानमंत्री की ठोस कूटनीति की वजह से ही संभव हो पाया है. यह अलग बात है कि कुछ घटनाएं चुनाव के दौरान ही हुई हैं, जिससे देश संभलकर चलने की कोशिश कर रहा है.

डॉ सतीश कुमार
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
singhsatis@gmail.com

भारत और फ्रांस के बीच बन रहे समीकरण का तत्कालीन कारण तो चीन है, लेकिन यह महज चीन तक सीमित नहीं है . नयी विश्व व्यवस्था में भारत और फ्रांस एक मिडिल किंगडम की भूमिका में हैं . फ्रांस यूरोप के लिए मिडिल पावर है, तो भारत एशिया के लिए .

बोधि वृक्ष

आत्मसमर्पण

जीवों की उत्पत्ति परमपुरुष से है और जीवों का अंत भी उन्हीं में होना तय है. संचरधारा- एक से अनेक में परमपुरुष से ही आते हैं और प्रतिसंचरधारा- अनेक से एक में यानि उन्हीं में मिल जाते हैं. आदि बिंदु और अनंत-बिंदु यद्यपि दोनों एक ही है. दोनों करते हैं- एकीभूत. किंतु प्रथम स्तर में मानव मन नहीं रहने के कारण मन वहां तक सोच नहीं सकता है. समाधि में मन का आलंबन हो जाता है. समाधि टूटने के बाद मनुष्य महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मन काम नहीं करता. मन तो परमपुरुष में लीन हो गया था. उस अवस्था में वैयष्टिक मन काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस अवस्था में मन में 'अनवस्था दोष' आ जाता है. मन है ही नहीं तो महसूस कैसे करेगा. इसलिए यह भी कहा गया है कि एक निश्चित बिंदु पर पंचभूत आये, यानी संचरधारा में पंचभूत संघर्ष तथा समिति के द्वारा जड़ पदार्थ चूर्णीभूत होकर मन में और फिर जीव आत्मा में रूपांतरित हो जाता है और वही जीवात्मा परमपुरुष की कृपा की बदौलत परमपुरुष में मिल जाता है. यही है सृष्टि का स्तर विन्यास. अंतिम गति के स्तर में उठता हुआ धीरे-धीरे जहां से वह आया था, वहीं लौट जाता है. सभी तरंगों की उत्पत्ति उन्हीं से और उन्हीं की प्रेरणा के रूपों में यह तरंगें, यह विभिन्न तरंगों के रूप में तरंगायित रूप सरल रेखाकार बनते हैं. परमपुरुष की कृपा पर यह विश्व ब्रह्मांड आश्रित है और उनकी कृपा पर ही सभी जीवित हैं, स्थित हैं और अंतिम स्तर में उनकी कृपा पर ही निर्भर रहेगा. मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार और उसकी अस्मिता अंत तक फेल कर जायेगी. इसलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है, जो शीघ्र उनकी कृपा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि परमपुरुष मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूं. तुम मुझे पराभक्ति दो. तुम मुझे शुद्धाभक्ति दो, जिससे इस मानव जीवन को मैं सफल कर सकूं. साधना द्वारा वे आत्मजगत की ओर चलते रहेंगे और चैत्तिक अनुभूति को 'अहं' में रूपांतरित कर देंगे अर्थात् मन के जड़ात्मक प्रतिफलन को मुक्त कर देंगे.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

आपके पत्र

एसिड अटैक के आरोपितों को मिले सख्त सजा

एसिड अटैक जैसी घटना मानवता को शर्मसार करनेवाली है. इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस को भी सजग होना होगा. साथ ही एसिड अटैक के आरोपितों को सख्त-से-सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस को आगे आना होगा. पुलिस महकमे को अपनी कार्यशैली की भी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबूत के अभाव में आरोपित कोर्ट से छूट जाते हैं. एसिड अटैक से पीड़िता का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है. इस तरह के अपराध को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है. क्योंकि हाल के दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, वह बदले की भावना से घटित हुई लगती हैं. इसलिए इनके लिए सख्त कानून के साथ आरोपितों की काउंसेलिंग की भी जरूरत है. महिलाओं को सुरक्षा व सम्मान के लिए समाज के हर तबके को आगे आना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी.

अवध किशोर कुमार, कहलगांव (भागलपुर)

ट्रैफिक नियमों का करें पालन, नहीं जायेगी जान

हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गयी है. ऐसे तो हर दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. इसमें चालकों की लापरवाही भी सामने आती है. तेज गति से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है. इससे हमारे देश के सकल उत्पाद के क्षेत्र में प्रति वर्ष तीन फीसदी का नुकसान होता है. कई बार युवाओं में स्टंट का बढ़ता क्रेज भी उन्हें दुर्घटना का शिकार बना देता है. हेलमेट और सुरक्षा नियमों का सही से पालन नहीं करने की वजह से भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है. कई बार यात्री तेज गति के कारण स्वयं से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं. हमें यात्रा करने के दौरान समय से ज्यादा आत्म सुरक्षा को तवज्जो देना चाहिए. यह कदम हमारे साथ कई जिंदगियां बर्बाद होने से रोक सकता है.

सुशील कुमार, पुनसुन (पटना)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षक निराश

बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित समान काम, समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिससे शिक्षकों में निराशा है. नियमित शिक्षकों से काफी वेतन मिलता है, जिससे घर चलाने में भी परेशानी होती है. इनका कहना है कि इसके लिए उनके बराबर ही काम करते हैं. पर, न्याय नहीं मिला. नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि नियमित और नियोजित शिक्षकों को अलग-अलग विद्यालय में पदस्थापित कर देना चाहिए. विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है. यहां का पठन-पाठन नियोजित शिक्षकों के भरोसे चलता है. यदि इनका हौसला टूट गया तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा. इसलिए नियोजित शिक्षकों के मान-सम्मान के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए.

टीपू चौधरी, बल्लीपुर (समस्तीपुर)

कुछ अलग

आम के स्वाद का रहस्य

मिथिलेश कु. राय
रचनाकार
mithileshray82@gmail.com

कक्का कह रहे थे कि पके फलों में थोड़ा-सा स्वाद उस वृक्ष का रहता है और थोड़ा-सा उसी वृक्ष के हरे पत्तों का. धूप जो बड़े प्यार से उसमें मीठापन भरती है, पके फलों में वह तो विद्यमान रहता ही है. साथ ही फलों से रगड़ खाती हवा भी अपना कुछ स्वाद उनमें डाल देती है. पके फलों में थोड़ा सा स्वाद मिट्टी का भी रहता है और जितना भी ठंडापन रहता है उनमें, वह सारा पाताल के पानी का रहता है. इस तरह पके फलों में थोड़ा सा स्वाद जड़ का भी रह जाता है! बात हरी मिर्ची से शुरू हुई थी और आम तक आ गयी थी. कक्का बिना हरी मिर्ची के एक बखत का भी भोजन नहीं कर सकते. थाली में एक तीखी मिर्ची हो तो वे कहते हैं कि खाने में जैसे कोई दिव्य स्वाद आ जाता है! लेकिन वे हाट-बाजार की मिर्ची कभी नहीं खाते. कहते हैं कि देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन स्वाद ठीक नहीं होता. मिर्ची का भी अपना एक खास स्वाद होता है और वह होता है उसका तीखापन. उनके अनुसार, हाट-बाजार की लंबी-लंबी मिर्ची से वे गुण छीन लिये जाते हैं. वे यह सवाल कर रहे थे कि अगर मिर्च खाने से तीखापन का बोध न हो, तो हम उसको कैसे परिभाषित करेंगे? कक्का बारहों मास मिर्ची के दो-चार पौधे लगाये रखते हैं. वे कहते हैं कि चाहूं तो थोड़ा-सा खाद दे दूं, जिससे पौधे रातों-रात बड़े हो जायेंगे. चाहूं तो ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर दूं कि अभी जो फल फूल छोड़ के निकला है, चार-पांच दिनों में लंबी-लंबी मिर्ची में बदल जायेंगे. लेकिन नहीं. तब मिर्ची मिर्ची नहीं रह जायेगी. अपनी तासीर के स्तर पर वह पता नहीं क्या हो जायेगी. जब कक्का यह सब कह रहे थे, मुझे वृंद का एक दोहा याद आ गया कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर. समय पाय तरुवर फरै, केतिक सींचौ नीर. कक्का आम के बारे में कहने लगे थे कि फलों को मिट्टी, पानी और धूप सिरजती हैं. समय आता है तो फल स्वतः पक जाते हैं और मीठे हो जाते हैं. लेकिन हम बाजार और उसके व्यवसाय की गिरफ्त में इस तरह फंस गये हैं कि उसके पकने और उसके मीठे होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते. हम कच्चे फलों को ही टहनियों से अलग कर देते हैं और उसे पकानेवाले रसायन में डाल देते हैं. कच्चे आम जिसे अभी पकने में महीना भर का समय लगता, वह दूसरे ही दिन पक कर पीला हो जाता है. बाजार में लोग उसे देखते हैं और उनका मन ललचने लगता है. वे उसे खरीदते हैं और खाते हैं. उन्हें कई बार यह लगता भी है कि पके आम का स्वाद ऐसा तो नहीं होता है. लेकिन वे ठीक से यह याद नहीं कर पाते कि पके आम का स्वाद कैसा होता है. आजकल लोग पेड़ पर ही पककर जमीन पर गिरे आम के स्वाद को भूल चुके हैं. कक्का कह रहे थे कि प्रकृति प्रदत्त ये अनमोल उपहार हमारे जीवन की रक्षा के लिए और हमारी स्वाद-ग्रंथियों की संतुष्टि के लिए हैं. लेकिन उसे जीवन से खिलवाड़ करनेवाली चीजों में बदल दिया गया है. वे कह रहे थे कि अब हम भोजन के माध्यम से पहले अपने शरीर में जहर भरते हैं, फिर जहर निकालने के उपक्रम में लगे रहते हैं.

देश दुनिया से

लंबे समय तक रहेगा चीन-अमेरिका ट्रेड वार का असर

ह्वाइट हाउस के मुख्य आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा है कि अमेरिका द्वारा चीन पर आयात शुल्क बढ़ाने से अमेरिका और चीन दोनों को कुछ नुकसान होगा. फॉक्स न्यूज को दिये इंटरव्यू में लैरी ने यह भी कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात को बल देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आयात शुल्क एक अच्छा विकल्प है, जो अर्थव्यवस्था की मदद ही करता है. अमेरिका-चीन के बीच चल रहा ट्रेड वार अप्रत्याशित है और वाशिंगटन अभी चीन को कोई रियायत देता नहीं दिख रहा है. शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया से पहले अमेरिका ने सोचा था कि चीन घुटने टेक देगा और ट्रेड वार के मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जायेगा. वाशिंगटन को उम्मीद थी कि शुल्क से आय के रूप में वह 100 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर लेगा. अमेरिका का यह भी दावा था कि शुल्क बढ़ाने से कई कंपनियां चीन छोड़ देंगी. लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. अपनी परेशानियों को लेकर चीन की सरकार सजग है, जबकि वहीं अमेरिका हेरफेर करने में लगा हुआ है. ऐसा माना जा रहा है कि इस ट्रेड वार का असर एक लंबे समय तक रहेगा.

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम